EDITORIAL

The Pain, Struggles, and Government Neglect of BSNL Employees

The Pain, Struggles, and Government Neglect of BSNL Employees* Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) is not merely a telecommunications company, but a strong backbone of the country's communication system. For years, BSNL employees have been providing communication services even in remote villages, border regions, hilly areas, and difficult geographical conditions across the nation. While private companies remained limited to profit-making regions, BSNL employees considered serving the country and its people their duty under all circumstances. Whether it was natural disasters, floods, storms, or any national crisis, BSNL employees have continuously worked day and night to maintain communication networks. Despite limited resources, outdated technical infrastructure, and an ever-increasing workload, employees never attempted to step back from their responsibilities. However, it is extremely unfortunate that these very employees, dedicated to serving the nation, are today themselves forced to struggle with economic, mental, and administrative hardships. Today, BSNL employees are bound by strict time regulations. Reaching the office on time, working late hours, achieving increasing targets, and handling multiple responsibilities have become compulsions for employees. But on the other hand, their legitimate problems and rights are continuously being ignored.Discipline and dedication are expected from employees, yet when it comes to their salaries, promotions, and facilities, the government and administration remain silent. The most serious issue is the long-pending wage revision. Even today, BSNL employees are compelled to work under the pay scale of 2007. **Despite nearly 16 years having passed, the new pay scale effective from January 1, 2017, has still not been approved by the Department of Telecommunications.** Amid rising inflation, children's education, medical expenses, family responsibilities, and increasing daily needs, the lives of employees are becoming extremely difficult. On one hand, the prices of all commodities in the market are rising, while on the other hand, employees' salaries remain trapped in the old structure. This is not merely an economic issue, but a matter connected to the self-respect and morale of employees. Employees who served honestly and faithfully for years are now being haunted by insecurity and worries about the future. Many employees are struggling to fulfill the basic needs of their families. Despite this, they continue to work tirelessly to keep the organization strong. **In October 2025, an agreement regarding wage revision was reached between the recognized unions and BSNL management. Subsequently, on February 12, 2026, the BSNL Board approved the proposal and forwarded it to the Department of Telecommunications.** Employees hoped that years of struggle would finally end and they would receive justice. But unfortunately, even after months, this important proposal remains pending at the departmental level. **This indifference from the government and the Department of Telecommunications is breaking the morale of employees.** Today, the number of employees in BSNL is continuously decreasing. New recruitment has almost stopped after retirements, due to which excessive workload has been placed on few employees. Along with technical work, responsibilities such as marketing, customer service, administrative tasks, and field duties are being assigned to the same employee. This is continuously increasing mental pressure on employees. The situation has become such that one employee is required to perform the work of several employees. Despite working day and night, employees are receiving neither adequate resources nor any

clear security for their future. Even though BSNL employees continue to work with complete dedication to save and strengthen the organization. NFTE BSNL clearly wishes to state that if BSNL is to be strengthened, then first its employees must be strengthened. The greatest strength of any organization is its employees. If employees' morale breaks, if they remain under economic and mental stress, then the development of the organization cannot be possible. The government and BSNL management should seriously understand the problems of employees and immediately approve the pending wage revision. Employees should be provided timely salaries and allowances, regular promotions, adequate staff, a respectful work environment, and social security. Doing justice to employees is not only an administrative responsibility but also a moral obligation. BSNL is not just a company, but a strategic and social necessity for the nation. Even today, BSNL's role remains most important in border regions, rural India, and crisis situations. If BSNL is weakened and its employees continue to be neglected, it will negatively impact the country's communication system as well. NFTE BSNL demands that the government and the Department of Telecommunications immediately accept the legitimate demands of employees. **The long-pending wage revision should be implemented without any further delay, and the injustice being faced by employees should end. BSNL employees are not asking for favors; they only seek their rights, dignity, and justice.** If the government truly wants to make BSNL strong and self-reliant, then it must first understand the pain, struggle, and sacrifices of BSNL employees. Because the future of BSNL can remain secure only through the trust, dignity, and morale of its employees. **"If BSNL survives, the nation's communication system will remain secure, and BSNL will become strong only when its employees receive justice, dignity, and security."**

संपादकीय

बीएसएनएल कर्मचारियों की पीड़ा, संघर्ष और सरकार की उपेक्षा

बीएसएनएल कर्मचारियों की पीड़ा, संघर्ष और सरकार की उपेक्षा भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) केवल एक दूरसंचार कंपनी नहीं, बल्कि देश की संचार व्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। वर्षों से बीएसएनएल के कर्मचारी देश के दूर–दराज गाँवों, सीमावर्ती क्षेत्रों, पहाड़ी इलाकों और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में भी संचार सेवाएँ उपलब्ध कराते आ रहे हैं। जब निजी कंपनियाँ केवल लाभ कमाने वाले क्षेत्रों तक सीमित रहीं, तब बीएसएनएल कर्मचारियों ने हर परिस्थिति में देश और जनता की सेवा को अपना कर्तव्य समझा। प्राकृतिक आपदाएँ हों, बाढ़ हो, तूफान हो या कोई राष्ट्रीय संकट हर स्थिति में बीएसएनएल कर्मचारी दिन–रात मेहनत कर संचार व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करते रहे हैं। सीमित संसाधनों, पुरानी तकनीकी व्यवस्था और लगातार बढ़ते कार्यभार के बावजूद कर्मचारियों ने कभी अपने दायित्वों से पीछे हटने का प्रयास नहीं किया। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि देश की सेवा में समर्पित यही कर्मचारी आज स्वयं आर्थिक, मानसिक और प्रशासनिक कठिनाइयों से जूझने को मजबूर हैं। आज बीएसएनएल कर्मचारियों पर समय की कठोर पाबंदी लागू है। समय पर कार्यालय पहुँचना, देर तक कार्य करना, बढ़ते लक्ष्य पूरे करना और कई प्रकार की जिम्मेदारियाँ निभाना कर्मचारियों की मजबूरी बन चुकी है। लेकिन दूसरी ओर उनकी जायज समस्याओं और अधिकारों की लगातार उपेक्षा की जा रही है। कर्मचारियों से अनुशासन और समर्पण की अपेक्षा तो की जाती है, किन्तु जब उनके वेतन, पदोन्नति और सुविधाओं की बात आती है, तब सरकार और प्रशासन मौन दिखाई देते हैं। सबसे गंभीर विषय वर्षों से लंबित वेतन संशोधन का है। बीएसएनएल कर्मचारी आज भी वर्ष 2007 के वेतनमान पर कार्य करने को विवश हैं। लगभग 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी 01 जनवरी 2017 से लागू होने वाले नए वेतनमान को अब तक दूरसंचार विभाग द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई है। लगातार बढ़ती महँगाई, बच्चों की शिक्षा, चिकित्सा खर्च, घर–परिवार की जिम्मेदारियाँ और दैनिक जीवन की बढ़ती आवश्यकताओं के बीच कर्मचारियों का जीवन अत्यंत कठिन होता जा रहा है। एक ओर बाजार में हर वस्तु की कीमत बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों का वेतन पुराने ढाँचे में जकड़ा हुआ है। यह केवल आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि कर्मचारियों के आत्मसम्मान और मनोबल से जुड़ा प्रश्न बन चुका है। वर्षों तक ईमानदारी और निष्ठा से सेवा देने वाले कर्मचारियों को आज असुरक्षा और भविष्य की चिंता सताने लगी है। कई कर्मचारी अपने परिवार की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके बावजूद वे संस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। अक्टूबर 2025 में मान्यता प्राप्त यूनियनों और बीएसएनएल प्रबंधन के बीच वेतन संशोधन को लेकर समझौता हुआ था। इसके बाद 12 फरवरी 2026 को बीएसएनएल बोर्ड ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दूरसंचार विभाग को भेज दिया। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि अब वर्षों का संघर्ष समाप्त होगा और उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि महीनों बीत जाने के बाद भी यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव विभागीय स्तर पर लंबित पड़ा हुआ

है। सरकार और दूरसंचार विभाग की यह उदासीनता कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ने का कार्य कर रही है। आज बीएसएनएल में कर्मचारियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। सेवानिवृत्ति के बाद नई भर्ती लगभग बंद है, जिसके कारण कम कर्मचारियों पर अत्यधिक कार्यभार डाल दिया गया है। तकनीकी कार्यों के साथ–साथ विपणन, ग्राहक सेवा, प्रशासनिक कार्य और फील्ड ड्यूटी जैसी अनेक जिम्मेदारियाँ एक ही कर्मचारी से कराई जा रही हैं। इससे कर्मचारियों पर मानसिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि एक कर्मचारी को कई कर्मचारियों का कार्य करना पड़ रहा है। दिन–रात की मेहनत के बावजूद कर्मचारियों को न तो पर्याप्त संसाधन मिल रहे हैं और न ही उनके भविष्य की कोई स्पष्ट सुरक्षा दिखाई दे रही है। इसके बावजूद बीएसएनएल कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ संस्था को बचाने और मजबूत करने में लगे हुए हैं। एनएफटीई बीएसएनएल स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि यदि बीएसएनएल को मजबूत बनाना है, तो सबसे पहले उसके कर्मचारियों को मजबूत करना होगा। किसी भी संस्था की सबसे बड़ी ताकत उसके कर्मचारी होते हैं। यदि कर्मचारियों का मनोबल टूट जाएगा, यदि वे आर्थिक और मानसिक तनाव में रहेंगे, तो संस्था का विकास संभव नहीं हो सकता। सरकार और बीएसएनएल प्रबंधन को चाहिए कि वे कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से समझें और लंबित वेतन संशोधन को तत्काल स्वीकृति दें। कर्मचारियों को समय पर वेतन एवं भत्ते, नियमित पदोन्नति, पर्याप्त स्टाफ, सम्मानजनक कार्य वातावरण और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कर्मचारियों के साथ न्याय करना केवल प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि नैतिक दायित्व भी है। बीएसएनएल केवल एक कंपनी नहीं, बल्कि देश की रणनीतिक और सामाजिक आवश्यकता है। सीमावर्ती क्षेत्रों, ग्रामीण भारत और संकट की परिस्थितियों में आज भी बीएसएनएल की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। यदि बीएसएनएल को कमजोर किया गया और उसके कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा होती रही, तो इसका दुष्प्रभाव देश की संचार व्यवस्था पर भी पड़ेगा। एनएफटीई बीएसएनएल सरकार और दूरसंचार विभाग से मांग करती है कि कर्मचारियों की जायज माँगों को तत्काल स्वीकार किया जाए। वर्षों से लंबित वेतन संशोधन को बिना किसी और देरी के लागू किया जाए तथा कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त किया जाए। बीएसएनएल कर्मचारी किसी पर उपकार नहीं माँग रहे, वे केवल अपना अधिकार, सम्मान और न्याय चाहते हैं। यदि सरकार वास्तव में बीएसएनएल को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाना चाहती है, तो उसे सबसे पहले बीएसएनएल कर्मचारियों के दर्द, संघर्ष और त्याग को समझना होगा। क्योंकि बीएसएनएल का भविष्य उसके कर्मचारियों के विश्वास, सम्मान और मनोबल से ही सुरक्षित रह सकता है। "बीएसएनएल बचेगा तो देश का संचार सुरक्षित रहेगा, और बीएसएनएल तभी मजबूत होगा जब उसके कर्मचारियों को न्याय, सम्मान और सुरक्षा मिलेगी।"